जरूर कहूंगा, और कल यहां यह चर्चा होने के बाद, मैंने खुद मुख्य मंत्री जी से बात की थी और वे बड़ी कृपा करके यहां आए थे। उनके साथ बात होने के समय हमने उनको बताया था कि दोनों सदनों के सदस्यों का कहना है कि मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी काफी नही है, जयुडिशियल इन्कवायरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी करने की बात मान ली। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य वहां गए थे, वहां के लागों ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे उसका नाम मिल जाए या उस अधिकारी का कैसा हुलिया था, यदि उसकी भी जांच के लिए कुछ करना होगा तो मैं करूंगा। अब अधिकारी के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात है, यहां डायरेक्शन जाती है कि इसके ऊपर एक्शन ले लो, उसके ऊपर एक्शन ले लो। न आप कहेंगे कि उनको देना चाहिए, मैं उनको कहूंगा कि जो जरूरी है, वह करना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई गलत बात हुई है तो उसको ढक कर नहीं रखना है और कोई ऐसी चीज भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से दूरगामी परिणाम हमारी आर्थिक उन्नति में, संबंधों में भी रह सकते हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKERJEE (West Bengal): Those workers who have been arrested should be released. It should be directed that without going into the case workers should be released. This should be first gesture. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will convey it to the Chief Minister. He will look into it. If they have been arrested and if some cases have been filed, I will convey to him as to how to deal with it.

MR. CHAIRMAN: Reply to the discussion on the situation arising due to drought and floods in various parts of the country raised by Shri Jayantilal Barot on the 26th July, 2005. When the House adjourned on the 26th July, 2005, the hon. Deputy Chairman announced that the discussion has been concluded and the concerned Minister will reply.

SHORT DURATION DISCUSSIONS

Drought and floods in various parts of the country—(contd.)

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : श्रीमन् कल जब यहां पर जो चर्चा हुई थी तब मैं इस सदन में उपस्थित नहीं था। उस समय दूसरे सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय मेरा वहां होना जरूरी था। यहां जो भी चर्चा हुई और जो भी मुद्दे यहां पर उठाए गए, मैंने उनको देखने की कोशिश की है। उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि चर्चा बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी अच्छी सूचनाएं देते हुए हुई है। इसके लिए मैं सारे सदस्यों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, शायद सारे मुद्दों का जवाब देना,

जवाबी भाषण संभव नहीं है, मगर हम उनकी गहराई में जाकर, देखकर जितने भी मुद्दों पर अमल कर सकते हैं, हम जरूर अमल करेंगे। कल जो चर्चा हुई, उस चर्चा में भाग लेते हुए

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी स्टेट के बारे में काफी कहा है कि उनकी स्टेट में बाढ़ की हालत कैसी रही, उससे कितना नुकसान हुआ और उनको किस प्रकार की मदद करनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने चर्चा की। हम यह बात ध्यान में रखेंगे और उस पर जो अमल करना है, वह करेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस साल खुशकिस्मती से सब तरफ बारिश ऐसी हुई है कि जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, वहां नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने का काम हमको करना पड़ेगा। मगर जहां पर बारिश ठीक हुई है, उसका फायदा भी हमको हुआ है। बारिश की वजह से जितने तालाब थे, वे पानी से भरे हुए नजर आते हैं। मुझे बताया गया है कि 98 प्रतिशत इस सीजन की बारिश इन दिनों में होगी। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। यह एक ऐसी बात है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, इसके लिए हमें दुख है, मगर हम सभी को मिलकर इस नुकसान को पूरा करना है। दूसरी तरफ अच्छी बारिश होने की वजह से, तालाब भरने की वजह से इस साल जो पीने के पानी या खेती के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है, वे दोनों आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। यह भी कहा जा सकता है कि अगर तालाब पूरी तरह से भर गए तो उसका उपयोग आने वाले दो सालों के लिए भी हो सकता है। इस साल की एक खासियत रही है कि दक्षिण हिन्दुस्तान में बारिश ज्यादा हुई है और उसके मुकाबले में उत्तर हिंदुस्तान में, जहां ज्यादा बारिश होती है, वहां पर शायद कम होती नजर आ रही है। हम हर साल जब बाढ़ और अकाल पर चर्चा करते हैं, तो सवाल आ जाता है कि किस हिस्से में अधिक बाढ़ आई है और किस हिस्से में अकाल है। अकाल का हिस्सा दक्षिण हिंदुस्तान का होता है और बाढ़ का उत्तर हिंदुस्तान का हिस्सा होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हमें देखने को मिली है कि इस साल यह बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। दक्षिण हिंदुस्तान में वर्षा ज्यादा हुई है और उत्तर हिंदुस्तान, जहां ज्यादा होती थी, वहां शायद उतनी वर्षा इस साल नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश और बंगाल के हिस्सों, असम, बिहार के कुछ हिस्सों में जरूर कुछ ज्यादा बारिश हुई है, मगर इस साल सबसे ज्यादा बारिश गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई है। इसके साथ-साथ महाराष्ट्र में भी दो दिन से बहुत जोरों से बारिश हो रही है, गोवा के अंदर भी ज्यादा बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से यहां पर काफी नुकसान होता नजर आता है। जिन प्रांतो में ज्यादा बारिश हुई है , अगर उनके नाम बताने हैं तो मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में ज्यादा बारिश हुई , मध्य प्रदेश में भी ज्यादा हुई है और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी काफी बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में भी इसका असर हुआ है और कुछ थोड़ा सा बिहार में भी हुआ है, यह मैं बता सकता हूं अगर इसके आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं इस प्रकार से बता सकता हूं कि कुल मिलाकर 131 जिलों में इसका असर

हुआ है। मैं प्रांतों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पूरे प्रांतो में बारिश नहीं है कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हुई , इसलिए मैं जिलों की बात बता रहा हूं। अब मैं तालुकों के बारे में बताना चाहता हूं। 131 जिलों में ज्यादा बारिश हुई है लेकिन जिन तालुको में ज्यादा बारिश हूई है उनकी संख्या 277 है। इसकी वजह से गांवों पर असर हुआ है। इनकी संख्या काफी है और यह संख्या करीब-करीब 16,000 है। यह 15,930 है। हम कह सकते हैं कि 16,000 गांवों में इस बारिश का ज्यादा असर हुआ है, बुरा हुआ है। इसमें कितनी लोक संख्या प्रभावित हुई है, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 54.54 लाख लोक संख्या प्रभावित हुई है, यानी करीब-करीब 55 लाख लोग इससे प्रभवित हुए हैं । यह संख्या भी काफी बड़ी है। इसमें जान का जो नुकसान हुआ है, मृत्यु की संख्या करीब-करीब 600 हैं इसमें 633 लोगों की जानें गई हैं । जो मवेशी इससे प्रभावित हुए हैं, वे भी बहुत हैं। 76,000 मवेशी इससे प्रभावित हुए हैं। जमीन का जो नुकसान हुआ है, वह पूरा मिलाकर, जो बताया गया है, वह करीब-करीब 7 लाख हेक्टेयर है। 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर इसका प्रभाव पड़ा है। इस पानी की वजह से जो घर बर्बाद हुए हैं, उनकी संख्या 2,83,000 है। अगर इसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर जगह पर काफी नुकसान हुआ है और इसका मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी करनी होगी।

सरकार ने क्या किया और खासकर प्रान्तों की सरकारों ने इस बारे में क्या किया? यह देखना जरूरी है। मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि सारे प्रान्तों की सरकारों ने अपनी पूरी ताकत लगा कर लोगों को मदद करने की कोशिश की। उनके पास जो यंत्रणा थी, उसका उपयोग किया। उनके जो अधिकारी थे, उनके पास जो साधन थे, उनके पास जो पैसा था, उनके पास जो नियोजन था, इन सारी चीजों का उन्होंने उपयोग किया। ज्यों ही ये हालात वहां पर पैदा हुए, वहां की सरकारों ने उन्हें मदद करने का काम किया। सबसे पहले उनका काम था कि जो लोग बाढ़ में अटके हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, अगर उनकी जान को कोई खतरा है तो उन्हें उस जगह से कैसे दूर निकाला जाए। यह सबसे पहली बात थी। उन्होंने और उनके अधिकारियों ने बड़े अच्छे ढंग से यह काम किया है।

उनके सामने दूसरा सवाल यह था कि जो लोग पानी से घिरे हुए हैं, उनके खाने का इंतजाम कैसे करना चाहिए? उन्होंने उन तक हवाई जहाज से, बोट्स से पकाया हुआ खाना पहुंचाया। वहां के लोग अपने सर पर भी खाना ले कर गए। इसके साथ-साथ लोगों ने बहुत सारी जगहों पर उनके खाने का इंतजाम किया। पीने के पानी का इंतजाम भी पैकेट्स में और बोटल्स में, जहां पीने का पानी नहीं था, वहां पर पहुंचाया गया है। उन्होंने उन्हें दवाइयां भी पहुंचायी थीं। केन्द्र सरकार की ओर से इसके बारे में जितनी भी उनकी मांगें थीं, वह हमने पूरी करने की कोशिश की।

उनकी सबसे पहली मांग थी कि जो लोग पानी से घिरे हुए हैं, उन तक अनाज पहुंचाने के लिए या उनको वहां से बचाने के लिए हेलिकॉप्टर की या हवाई जहाज की जरूरत है, तो वह हमने उनको

दिया और उन्होंने उसका उपयोग किया। इसके बाद उनकी मांग थी कि उन्हें बोट्स चाहिए और उन्हें वे भी दिए गए। नेवी के पास जो बोट्स थे, वे उन्हें दिए गए। हमने खास कर उत्तर हिन्दुस्तान में बहुत सारे बोट्स रखे हुए हैं। बिहार के अन्दर, अरुणाचल प्रदेश के अन्दर, असम के अन्दर जब बाढ़ आती है, जो उन बोट्स का उपयोग किया जाता है। मगर खुशकिस्मती से इस साल वहां पर बाढ़ नहीं थी और वहां पर बोट्स थे। वे बोट्स हवाई जहाज में रख कर गुजरात और मध्य प्रदेश पहुंचाए गए और उन बोट्स का वहां पर उपयोग किया गया।

वहां से अनाज की कोई मांग नहीं थी, क्योंकि उनके पास अनाज था, मगर दवाइयों की मांग थी। हम उनकी दवाइयों की मांग भी पूरी कर सके, हम उन्हें दवाइयां दे सके। जब यह हो रहा था, तब हमारे केन्द्र के मंत्रीगण और पक्ष के नेता भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनके साथ बात की। जब उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने जितना भी पैसा मांगा था, हमने उतना देने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में बहुत बाढ़ आई है, वहां पर तिब्बत में जो डैम है, उसके टूटने की वजह से और वर्षा होने की वजह से भी बाढ़ आ गई। उन्होंने जो पैसा मांगा था, वह उनको दो किश्तों में दिया गया। गुजरात ने भी जो पैसा मांगा था, वह उनको दिया गया और जो पैसा मध्य प्रदेश ने मांगा था, उनको भी हमने दे दिया। दूसरे प्रान्तों से पैसों की मांग जैसे-जैसे आएगी, वह हम देख कर करेंगे। पैसा देने का काम हम तीन तरीके से कर रहे हैं। एक स्कीम यह है जिसके द्वारा फाइनांस कमीशन से जितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए कहा गया है, वह पैसा उनको मांगते ही इम्मेडिएटली दिया जाता है। दूसरा है नेशनल केलामिटी फंड से जो पैसा दिया जाना है, जब वह पैसा काफी नहीं होता है, तो ज्यादा पैसे की मांग होती है और उस पैसे की पूर्ति यहां से करना जरूरी हो जाता है। महोदय, उसमें कोई टीम वहां पर जाती है, देखती है कि कितना नुकसान हुआ है और आकर कहती है कि इतना नुकसान है, इतनी मांग है, इतना पैसा उनको देना चाहिए। मगर हम इस समय ऐसी formality में भी नहीं जा रहे हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने बताया कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है; 5000 करोड़ रुपयों की जरूरत है। हमने 500 करोड़ रुपए उनको दे दिए, मगर हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना नुकसान हुआ है कि पहली किस्त जो गई है, वह भी काफी नहीं है। दूसरी किस्त जो हमने दी है, शायद वह भी काफी नहीं होगी। उससे भी ज्यादा पैसे की मांग उधर से आ सकती है। कल शायद यही बात यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने अपने भाषण में बतायी है। हम सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी मांग उनकी तरफ से आएगी-वह चाहे सड़क दुरुस्ती के लिए हो या घर बाँधने के लिए हो या पीने का पानी देने के लिए हो या बिजली की व्यवस्था करने के लिए हो या स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, हमें उसकी भी व्यवस्था देश की मदद लेकर करना जरुरी है। मगर वह थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाएगा। जब यहाँ पर सुनामी आई तो हमनें क्या किया था? हमने पहले आदमियों को बचाया, खाना खिलाया, बाद में थोड़ा पैसा दिया, बाद में थोड़ा और पैसा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी

का गठन किया और उनको कहा कि आप वहां जाइए और देखिए कि कितनी मील सड़कें उनकी नादुरुस्त हुई हैं, कितनी बिजली का नुकसान हुआ है, कितने घर गिरे हैं? आप उसका मुआयना कीजिए और हमें बताइए कि हम इसको किस प्रकार से करें। हमनें प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक कमेटी बनाकर उस कमेटी के सारे एक्सपर्ट्स को बिठाकर और उनसे अंदाजा लेकर वह रकम कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनको देने की एक कोशिश की है। सुनामी में हम लोगों ने यहां से 10 हजार करोड़ रुपए तक मदद की है। यह पहले फेज का जो काम है-लोगों को बचाना और लोगों को खाना देना-मेरे ख्याल से यह काम गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और असम में हुआ है। आज शायद यह काम महाराष्ट्र और गोवा के अंदर चालू है। वहां पर भी बहुत से लोगों की जानें गई हैं। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर करीब-करीब 50 लोगों की जानें गई है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय राजाराम राउत (महाराष्ट्र): महोदय, 50 लोगों की नहीं बल्कि 300 लोगों की जानें गई है।

श्री शिवराज वी.पाटिल: ठीक है, हम ऐसी प्रार्थना करेगें कि इतनी जानें नहीं जाएं। अगर यह सही है तो उसके लिए भी मदद करेगें। सही आंकड़ा क्या है, वह हम देख लेगें कि वहां कितना उसका नुकसान हुआ है। हमने वहां पर भी हेलीकॉप्टर्स भेजे है, नेवी के बोट्स भेजे है और आर्मी के कॉलम्स भी भेजे है और उनको कहा है कि आपको जिस चीज की भी जरुरत हो, हम यह है उसकी मदद करेंगें। इस प्रकार से वह काम करेंगें। दूसरे फेज का काम भी काफी अहमियत रखता है। दूसरे फेज में यह देखना जारी होता है कि वहां कोई महामारी नहीं फैले। कोई ऐसी बीमारी नहीं फैले जिसकी वजह से लोगों पर असर हो जाए। जो मरे हुए मवेशी या मनुष्य हैं, उनको वहां से निकालना, उनको दफनाना या जलाना बहुत जरूरी हो जाता है। वह काम भी कुछ प्रांतों में हुआ है और दूसरे प्रांतों में भी जरूर किया जाएगा। उसके साथ-साथ तीसरा काम जो वहां करना जरूरी होता है कि जिनके घर गिरे और मैंने आपको आंकड़े दिए कि कितने घर गिरे हुए हैं। वहां पर जो घरों का नुकसान हुआ है करीब-करीब 3 लाख घर गिरे हुए है। अब इन 3 लाख घरों में रहने वाले लोग, जिनके घर गिर गए हैं, उनके टेम्परारी शेल्टर का काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने प्रांत की सरकार से कहा है कि आप जिस प्रकार से वह काम करना चाहतें हैं, कीजिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर आप रख सकते हैं तो वह कीजिए या आप टेम्परारी शेड बनाने का काम कर सकते हैं तो वह भी कीजिए। सुनामी जब हुई तो टेम्परारी शेड बनाने का काम भी किया गया था। जब अर्थ क्वेक हुआ तो उस समय भी यह काम किया गया था। इसी प्रकार से उसका भी काम करने के लिए उनको कहा गया है और यह काम कुछ प्रांतों में चालू है और दूसरे प्रांतों में भी चालू हो जाएगा। यह तीसरा फेज बहुत रकम मांगता है और इस काम को बहुत गहराई में जाकर, सोचकर करना पड़ेगा। एक बात तो यह है कि अगर नदी के किनारे किसी के घर है और वहां पर बार-बार बाढ़ आती है जिसमें

उनके घर बह जाते हैं, उनकी जान और माल का नुकसान होता है, तो यह देखना पड़ेगा कि वे घर किस जगह पर बनाए जाएं। वहीं बनाए जाएं या और कहीं बनाए जाएं, यह देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पीने के पानी की दिक्कत हर जगह पैदा हुई है। इसलिए वहां पर पीने के पानी की कमी को किस प्रकार से पूरा करना है इसको भी देखना जरूरी हो जाएगा। तीसरी बात जो है, वह यह है कि वहां पर अगर स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है, या हास्पीटल की बिल्डिंग गिर गई है, तो उसको भी तैयार करना है, यह देखना पड़ेगा। इसके हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को कहेंगे कि हर प्रांत के साथ बैठकर इन सारे विभागों में उनका कितना नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी लेकर देखे कि उन्हें कितने पैसे की जरूरत है, कितने दिन में उसे बनाएंगे, किस प्रकार से नई टैक्नोलोजी का उपयोग करके बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक कमेटी बनाकर इसका विचार करेंगे। अब उसमें प्रांत की सरकार अपना कितना हिस्सा उठा सकती है, वह भी देखेंगे और केन्द्र की सरकार से उसमें कितनी मदद करनी है, वह भी हम देखेंगे। यह जो रिहैब्लिटेशन का काम है, इसको हम करेंगे।

श्रीमन् यह जो बाढ़ का मामला है, इसके संबंध में संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे डिटेल्स के मालूमात दिए जा सकते हैं, आंकड़ें भी दिए जा सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वे सारे आंकड़ें देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से अपने प्रांत के बारे में जानते हैं। अगर वे चाहें, तो मैं दूसरे प्रांतों का लिखित रूप में उनको दे दूंगा। हमारे देश में इस बात का सोचना जरूरी है कि हमारा यह देश इतना बड़ा है, यहां हर साल किसी न किसी प्रांत में बाढ़ आती है, हर साल किसी न किसी प्रांत में सूखा पड़ता है और हर साल इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिए और सूखे से लोगों को बचाने के लिए हमें कदम उठाने पड़ते हैं। इसके लिए एक स्थाई व्यवस्था का होना आवश्यक है। सवाल यह है कि स्थाई व्यवस्था क्या हो सकती है? इस स्थाई व्यवस्था के लिए कदम उठाना जरूरी है और खुशकिस्मती यह है कि पहले जो रिकार्ड आए थे उसके आधार पर, आज जो विचार हो रहा है उसके आधार पर भी और सुनामी के बाद उसकी तीव्रता को जानते हुए हम लोगों ने कदम उठाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात हमने जो की है, वह है नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी निर्माण करने की। आज संसार में अलग-अलग देशों में इसके ऊपर विचार किया गया है और हर देश में इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की अथोरिटी, एक प्रकार का इंस्टीटयूशन बनाया गया है, जो इस प्रकार की आपदा आने पर ही विचार नहीं करती बल्कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसका कैसे मुकाबला करना है, उसकी पहले से ही तैयारी करती है। यह जरूरी है और इसलिए हमने अपने देश में अगर बाढ़ आए तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, अगर सूखा आए तो उसका कैसे मुकाबला किए जाए, अगर भूकंप आए तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, अगर लैंड-स्लाइड हो तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, अगर अवालांच (avalanche) हो तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए

या साइकलोन आए तो उसका कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर विचार करने के लिए यह अथोरिटी बनाई है। इसके मैम्बर भी अपायंट हुए हैं और उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है। जब ये सदस्य बैठेंगे, तो सोचेंगे कि हमारे देश के किस हिस्से में हमेशा बाढ़ आती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं और कुछ दूसरे प्रांतों के ऐसे हिस्से हैं, जहां हर साल बाढ़ की आपदा का सामना वहां के लोगों को करना पड़ता है, उन इलाकों को क्या मदद करनी है, इसकी पूरी तैयारी करनी है। वहां पर सिर्फ बोट देना है, इतना ही काफी नहीं है बल्कि वहां पर गांव कैसे बसाना है, कहां बसाना है, यह भी देखना है। अगर बाढ़ आने के बाद वे गांव पानी से घिरे रहने वाले हैं तो घिरे रहने वाले दिनों में वहां अनाज की कमी न हो, इसके लिए ग्रेन-बैंक्स या गोदाम रखकर किस तरह उनकी मदद करनी है, यह भी हमें देखना है। इसके लिए यह अथॉरिटी बनाई गई और इस अथॉरिटी का काम शुरू हो गया है। हम यह चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में भी इस प्रकार की अथॉरिटी बनाई जाए। गुजरात सरकार ने इस प्रकार की अथॉरिटी बनाई है। वहां पर जब भूकम्प आया तो उनको यह मालूम हुआ कि भूकम्प आने के बाद तैयारी करना ठीक नहीं है, भूकम्प आने से पहले तैयारी करनी जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक स्टेट अथॉरिटी वहां पर बनाई है। सिर्फ स्टेट की ही अथॉरिटी नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कानून भी बनाया है। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी हुआ। वहां पर जब साइक्लोन आया और वहां लोगों का नुकसान हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसा मौका आने पर काम शुरू करने की बजाए ऐसा मौका आने से पहने ही काम शुरू करें। उन्होंने उसके लिए कदम उठाए हैं। हमने दूसरे प्रान्तों को भी कहा है कि आप भी इस प्रकार की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाइए और चाहें तो आप कानून भी बनाएं और यह प्रयास हो रहा है कि हम जो यहां पर कानून लाए हैं, वह आपके सामने जरूर आएगा, वह स्टैंडिंग कमेटी के सामने है और वह आएगा तो उससे हमको बहुत फायदा होगा। उसमें मैन मेड डिजास्टर और नेचर मेड डिजास्टर, इन दोनों को अलग-अलग करके सोचना है। मैन मेड डिजास्टर में अगर न्यूक्लिअर या रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हुआ तो क्या करना है, बायोलॉजिकल डिजास्टर हुआ तो क्या करना है या कैमिकल डिजास्टर हुआ तो क्या करना है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा और नेचर डिजास्टर में फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन वगैरह, वगैरह हैं, इसके बारे में क्या विचार करना है, यह सोचा जाएगा। यह काम यहां पर शुरू हो गया है और पूरे संसार के अंदर दो चीजों में आज चर्चा चल रही है, जिसमें कोआपरेशन की बात की जा रही है-एक है डिजास्टर मैनेजमेंट में कोआपरेशन और दूसरी है टेरेरिज्म का मुकाबला करने के काम में कोआपरेशन, इन दोनों चीजों में कोआपरेशन करने की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल लैवल पर जो रहा है, उसमें भी हम शरीक होना चाहते है। थाइलैंड वगैरह में जो इंस्टिट्यूशंस हैं, उनके भी हम मैम्बर बन गए हैं, दूसरे जो वैस्टर्न कंट्रीज में हैं, उनके भी मैम्बर बन गए हैं और इस प्रकार से उसकी हम तैयारी कर रहे हैं।

यहां पर मैंने कल सुना कि बहुत सारे सदस्यों ने दो बातों पर बहुत जोर दिया–एक बात तो यह थी कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए आप प्लान बनाइए और दूसरी बात थी कि रिवर शुड बी लिंक्ड। यह बात उन्होंने यहां पर कही। बहुत सदस्यों ने इस बात को दोहराया, इस बात को कहा, ऐसा मैंने पढ़ा । हम यह कहना चाहते हैं कि इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको हम यह जरूर देखने के लिए कहेंगे कि जहां पर फ्लड आते हैं, उससे राहत देने के लिए, उससे लोगों का नुकसान न हो, यह देखने के लिए जहां तक हो सके, जल्दी से जल्दी वह वहां पर डैम बनाए। यह काम हमें फुटहिल्स ऑफ हिमालय में करना जरूरी है औरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर भी करना जरूरी है। वहां पर अगर हम प्लान बनाएं तो यह पानी कम हो जाएगा। इसमें एक अड़चन यह आ रही है कि बाहर से जो नदियां आती हैं, जैसे नेपाल से या दूसरी जगहों से आती हैं, उस देश के साथ भी समझौता होना बहुत जरूरी है। जो सरकारें आज तक यहां पर रही हैं, उन्होंने कोशिश की है, उसमें जितना भी हो सकता है, उसके आधार पर करेंगे, मगर हमारे देश के अंदर जहां पर भी यह पानी आता है, पहाड़ियों से, झरनों से, हिमालय से और घाटों से पानी आता है, उसको रोककर बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, यह हम जरूर देखेंगे। दूसरी जो अहम बात है, जिस पर सारे सदन में और सारे देश में सहमति होना जरूरी है और सहमति के बिना काम आसानी से नहीं होगा, वह लिंकेजिस ऑफ रिवर। यह बात सही है कि हिमालय से निकलने वाली जो सारी नदियां हैं या वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो सारी नदियां हैं, बारिश के दिनों में उनमें पानी बहुत होता है और उसे रोकने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वह पानी समुद्र में चला जाता है एवं उस पानी का उपयोग हम लोग नही कर पाते हैं। इसे लिंक करने का विचार बहुत दिन से चल रहा है। मैं तो समझता हूं कि 1960 के दशक में भी, 1966 के जो चुनाव हुए या 1972 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भी यही बात उठाई गई थी और मेनिफेस्टो में भी लिखा गया था। पिछली सरकार जो कि एन॰डी॰ए॰ की सरकार थी, उसने भी इसी बात को अपनाया था और इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि इसके बारे में तैयारियां हो रही है। पहले तो हमें यह देखना है कि कितना पानी समुद्र में जाता है। दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि जहां से नदियां हो कर जाती हैं, उस प्रान्त के लिए कितना पानी आवश्यक है, क्योंकि उस प्रान्त को प्यासा रख कर उस प्रान्त का पानी दूसरी जगह ले जाया जाए, यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार उस प्रान्त की कितनी जरूरत है उसे देखना होगा। तीसरी चीज हमें यह देखनी होगी कि इसमें लगने वाली जो टेक्नॉलाजी है, वह किस प्रकार की होनी चाहिए और इस पर जो पैसा लगने वाला है, उसकी कितनी जरूरत है। मुझे आज बताया गया है कि करीब–करीब सात लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है और अगर आज ही यह काम शुरू किया जाए और तुरन्त खत्म हो जाए तो उसके लिए सात लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आज खत्म नहीं हुआ और पांच या दस साल में खत्म हुआ तब यदि हर वर्ष का 12 प्रतिशत एस्केलेशन हम डालें तो उसकी कीमत 15 से 20 लाख करोड़ तक हो सकती है।

पिछली सरकार ने कहा था कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पुराने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, वे भी जानते है और हम भी जानते है कि जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो दुनिया के फाइनान्शियल इन्स्टीट्यूट पैसे देने के लिए तैयार होते हैं एवं कम इंटरेस्ट पर देने के लिए तैयार होते हैं और जब पैसा आ जाता है तो उसका उपयोग हो जाता है। मेरे ख्याल से पैसे की उतनी परेशानी नहीं होगी, पैसा तो आएगा ही, इसके लिए पैसा तो मिलेगा ही, इसके लिए शायद टेक्नॉलोजी की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो आवश्यकता है समझदारी की और दूसरी आवश्यकता है कोऑपरेटिव साइकॉलाजी निर्मित करने की। उसके बिना सह कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक प्रान्त के लोगों को सह बताना जरूरी है कि उन्हें जितना पानी चाहिए, उससे ज्यादा उनके लिए रखा जाना चाहिए, ताकि आने वाले 10-15 साल में भी वह पानी उनको कम न पड़े, वहां पर इतने पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भी यदि पानी समुद्र में जा रहा है तब उस पानी को दूसरी तरफ ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। संसार एक है और देश तो एक है ही, इस प्रकार पानी की समस्या का निदान हो सकता है।

आज बहुत-से लोग यह कहते हैं कि पानी की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी खत्म हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चलेंगीं। मैं इन दोनों ही विचारों से सहमत हूं। मेरा मानना तो यह है कि हमारा जो ग्लोब है two-third of it is water. जब दो तिहाई पानी है तो पानी की किल्लत कैसे हो सकती है, कमी कैसे हो सकती है? यदि कमी होगी तो हमारे ज्ञान की होगी और हमारी क्षमता की होगी जिसके आधार पर समुद्र का पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए हम ला सकें। आज जरूरी यह है कि हम एक ऐसी टेक्नॉलाजी निर्मित करें जिससे कि कम कीमत में समुद्र का पानी पीने के लिए एवं इरिगेशन के लिए हम दे सकें। एनर्जी की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है, every matter is energy and energy is matter, वह तो इंटरचेंजेबल है। यह संसार एनर्जी और मैटर दोनों में ही है, न तो एनर्जी कम पड़ने वाली है, न पानी कम पड़ने वाला है यदि कुछ कम पड़ेगा तो हमारा ज्ञान कम पड़ेगा और यदि हम उसे बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। उससे भी ज्यादा आवश्यकता आज एक-दूसरे के साथ सहकार करने की है। एक प्रान्त का आदमी, दूसरे प्रान्त के आदमी को अपने घर का ही माने, ऐसी जरूरत है, तभी यह हो सकता है, अन्यथा यह नहीं हो सकता है और वह किस प्रकार से करना है, इसे हमें देखना होगा। यह तो बहुत आसान है कि किसी भी मुद्दे पर हम एक को दूसरे से अलग कर सकें, प्रान्त के नाम पर, भाषा के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, किसी भी नाम पर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग मिल जाएं और जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हो सकता है, यदि हम ऐसा मान लें तो ये सारे प्रश्न हल हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं और इस प्रकार का वातावरण नेशनल डेवलेवमेन्ट एथॉरिटी में निर्मित नहीं होगा। इस प्रकार का वातावरण हो सका तो राज्य सभा में और लोक सभा में होगा, बाहर होगा, हमारी मस्तिष्क में वह निर्माण होना चाहिए। तो शुरूआत का तो काम है वह प्रान्त की सरकारें करेंगी, उसके बाद का जो काम है हम सब

लोग मिलकर करेंगे और उसके बाद का तो काम है हमको राज्य सभा और लोक सभा में और बाहर करना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण लेकर हम कर रहे हैं। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा का प्रश्न हो या बाढ़ का प्रश्न हो, हमारे लोग इतने सक्षम हैं, हमारे देश की ताकत इतनी है, ऊपरी तौर पर हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर भी आते हैं तो मन से हम सब लोग एक हैं और इसकी वजह से कोई संकट आ जाए, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ संकट आ जाए या नियति द्वारा बनाया हुआ संकट आ जाए उसका हम मुकाबला कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रान्त की सरकारों ने जो काम किया और हम भी अपनी तरफ से यहां से कोई कमी नहीं करेंगे। जो भी हम यहां से कर सकते हैं करने की जरूर कोशिश करेंगे, इतना ही मैं इसके उत्तर में आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल): मान्यवर, मैंने कल एक मुद्दा उठाया था जिसका ताल्लुक सीधा-सीधा बाढ़ के साथ नहीं था लेकिन बाढ़ के वक्त वह होता है और वह सिर्फ हमारे पश्चिमी बंगाल में होता है, वह है रिवर इरोजन और इस रिवर इरोजन की वजह से जो मैंने कल विस्तार में बताया था, हमारे तीन डिस्ट्रिक्ट के हर साल दो-तीन-चार गांव नदी में बह जाते हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): बिहार में भी होता है।

श्री शंकर राय चौधरी: बिहार में भी होता है, असम में भी होता है। लेकिन हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं। बिहार में है, असम में है और यह मेरा ख्याल है कि अभी तक इसे फ्लड या नेशनल कैलेमिटी में रखा नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि रिवर इरोजन से जो हर साल नुकसान हो रहा है, कम से कम मैं अपनी स्टेट के बारे में बोल रहा हूं, दूसरी स्टेट में भी यही हाल होगा। मैं मानता हूं कि यही हाल होगा। हर साल दो-तीन-चार गांव नदी में बह जाते हैं और नेशनल कैलेमिटी फंड से इनको कोई रिलीफ मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि हालांकि इस पर चर्चा 1996 में चली थी, उसके बाद कम से कम हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ, खास काम नहीं हुआ है। हर साल यह होता रहता है, हर बारिश के मौसम में यह होता रहता है और सुनते हैं कि मदद की जाएगी, पर वह मदद नहीं हो रही है। सिर्फ रिवर इरोजन नहीं, उसके साथ-साथ जो गांव बह जाते हैं, जमीन बह जाती है, फसल बह जाती है उसका जो मुआवजा या कैलेमिटी फंड की तरफ से भी जो रिलीफ दिया जाता है वह सही ढंग से नहीं आता। तो हम चाहेंगे कि यह एक बहुत पिक्यूलियर इसको बाढ़ कहिए या कुछ कहिए, लेकिन इरोजन जो हमारी समस्या है, इस पर ध्यान दिया जाए। हमने यह सुना हुआ है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुछ प्रबंध किया गया है, सुना था साढ़े नौ सौ करोड़ का था, अभी 1996 का फिगर था, अब जरूर बढ़ गया होगा, अगर 12 परसेंट लगाते हैं तो जरूर बढ़ गया होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम दसवीं परियोजना के अन्तर्गत जिसके लिए अभी दो साल रह गए हैं, यह जो आफत हमारे ऊपर हर साल आती है, हमारे स्टेट में इसको खत्म किया जाए और हम चाहते हैं कि इसको एक नेशनल प्रोब्लम के तौर पर लिया जाए। इस पर हमारे स्टेट ने बार-बार बोला है । बिहार ने भी बोला होगा, असम ने भी बोला होगा, इसको नेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर लिया जाए, क्योंकि इस पर जितना ध्यान देना चाहिए, वह नहीं हो

रहा है क्योंकि यह बड़ा पिक्यूलियर प्रोब्लम है। हम चाहते हैं कि दसवीं परियोजना के अंदर इसका कोई हल निकाला जाए। धन्यवाद।

1.00 P.M.

SHRI NILOTPAL BASU: (West Bengal): Sir, I would just submit one point. I think the question relating to river erosion is also now a part of the National Common Minimum Programme. The basic problem is that all those rivers in the East are international rivers. So, it really needs an integrated river management with neighbouring countries also, and this has now been recognised in the Common Minimum Programme. But somehow, the commensurate financial allocation is not there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only clarifications, please. No speeches.

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): उपसभापति महोदय, मुझे एक क्लेरिफिकेशन पूछना है कि गुजरात सरकार की तरफ से 8100 करोड़ रूपये की मांग की गई थी, क्योंकि वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वहां पर जो सेंट्रल टीम गई, उसने गुजरात के लिए कितनी रिलीफ रिकमंड की है, इसके बारे में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं। केन्द्र सरकार की तरफ से केवल 500 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, परन्तु गुजरात सरकार ने 8100 करोड़ रुपये की मांग की है, सेंट्रल कमेटी की तरफ से, उनको कितनी रिलीफ दी जा रही है।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करते हुए बताना चाहता हूं कि वहां की स्थिति, अन्य नदियों में जिस तरह की बाढ़ आती है, उससे भिन्न है सतलुज नदी का इतिहास कभी भी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष अथवा दो वर्ष पूर्व जो बाढ़ आई थी, उसके कारण क्या हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स का बह जाना है अथवा पारचू झील जो तिब्बत में स्थित है, क्या वहां पर लैंड स्लाइड के कारण वह झील बंद हुई है अथवा वह झील जानबूझकर बंद की गई है और हिमाचल प्रदेश तथा भारत के लिए एक प्रकार से यह चीन का पानी का मिसाइल तो बनने वाला नहीं है? क्योंकि यदि ज्यादा पानी इस झील से आ गया, तो उससे भाखड़ा डैम को नुकसान हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का चीन सरकार के साथ इस सतलुज नदी में बाढ़ आने के कारण की जानकारी के लिए हिन्दुस्तान से कोई डेलीगेशन भेजने का विचार है? क्या उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के एक्सपर्ट्स और भारत सरकार के एक्सपर्ट्स वहां जाकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो सतलुज नदी में तीन वर्ष से बाढ़ आ रही है, उसके पीछे कारण क्या हैं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मगर कल से मुम्बई में बारिश के कारण जो प्राब्लम्स हैं, वहां पर हम सब के घर

अंडर वाटर हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या आपने कुछ सोचा है, क्या आप इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप पूछिए। आप पूछिए। ...(व्यवधान)... वह जवाब देंगे। श्री शरद जोशी। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: मैं श्री जय राम रमेश जी की टिप्पणी को सुनना चाहती हूँ...(व्यवधान)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, yesterday's debate was largely addressed to the Minister of Food and Agriculture. At least two or three Members including Hon. Shri Jairam Ramesh and myself had asked pointed questions relating to agriculture. I have a lot of respect for the Minister of Home Affairs who has given an excellent reply that covers the Home Ministry's aspect of the drought and flood situation. Since the Minister of Food and Agriculture is present here, I was wondering if he would be completing the reply by addressing to the questions specifically posed to him.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, yesterday I had pointed out one problem. In Tripura, the rivers are flowing from upstream to Bangladesh; and we had seen that when we wanted to implement an irrigation scheme in Belonia, Bangladesh had objected and that scheme could not be implemented. Secondly, in Bangladesh, because of floods, they have made some protection dam and that is why the water is blocked in our State; it takes a long time for the water to flow from there. So, these are the problems. I want to know whether these problems can be taken into consideration. Thirdly, in the last year, our State was affected badly due to floods. The State Government had proposed a relief fund of Rs. 75 crores but only Rs. 5 lakh has been given to the State. It is not a wise thing to deprive a State of the North-East which is a Special Category State. I want to know from the hon. Minister whether this issue would be given due consideration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It should not become another debate. Now, Mr. Sanjay Raut. Just put questions. (*Interruptions*)

श्री संजय राजाराम राउत: सर, मैं मुम्बई से हूं लेकिन मुम्बई का जैसा ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, yesterday, 19 Members participated in the debate. Again, today 19 more Members are going to seek clarifications. (*Interruptions*)

श्री संजय राजाराम राउत: सर, दो दिन से पूरी मुम्बई पानी के नीचे है ओर कोंकण एरिया में

कल से तीन सौ से ज्यादा लोग बह गए हैं। पूरा महा ताल्लुका जो है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सौ से ज्यादा गांव बह गए हैं। मुझे लगता है कि वहां अभी तक सैंटर की ओर से किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे जो जानकारी है ...(व्यवधान)... राज्य सरकार से भी संबद्ध है, लेकिन आप सैंटर की बात कर रहे थे। वहां अभी तक मदद नहीं पहुंची है। मुम्बई की हालत अगर आप देखेंगे तो कल से पूरी मुम्बई रास्ते पर है, घर-घर में पानी गया है और किसी भी प्रकार की मदद मुम्बई को नहीं मिल रही है। मुम्बई के महत्व को जानते हुए वहां ज्यादा से ज्यादा मदद आपसे मिलनी चाहिए, यही मेरी मांग है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I want to seek one clarification. The hon. Minister for Agriculture is here and he will be replying to various issues raised by the Members. Sir, yesterday, 19 Members who spoke on this subject laid emphasis on just one point. What was that point? The point was to have a long-term solution on floods and droughts. That point is very important. What is the solution, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are making a speech. Give him the solution.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: What the hon. Minister should clarify is, how he is going to store the rain water so that it could be used at the time of drought. That is the main point. The main point is inter-linked with the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance and the Ministry of Water Resources. All the three Ministries must coordinate, and on their behalf, the Agriculture Minister should give a reply.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): महोदय, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री मंगनी लाल मंडल: कुल दो-तीन बिन्दु हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप ज्यादा प्रश्न करेंगे तो भाषण हो जाएगा।

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, मैं तो बिहार से आता हूं जहां हर वर्ष भंयकर बाढ़ आती है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि कुछ बिन्दुओं की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर जवाब दे। श्री चौधरी जी ने कहा कि जहां बाढ़ आती है, वहां इरोज़न का मामला, यानी कटाव का मामला इसमें निहित रहता है। कटाव की समस्या के बारे में जो उन्होंने बंगाल के संदर्भ में कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा मैं दो बिन्दुओं की ओर ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अपने जवाब में कहा है और विशेषकर बाढ़ नियंत्रण के मामले में उन्होंने केवल दो मुद्दों का उल्लेख किया है। एक मुद्दा है कि डैम बने-अब डैम तो पहाड़ी इलाके में बनेंगे, नेपाल में बनेंगे-यह ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि नदियों का अंतर्मिलन हो, इंटर लिंकिंग हो। लेकिन तीसरी व्यवस्था और है, जो पहले से वैज्ञानिक व्यवस्था है- जिस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा, मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान उससे हट रहा है- कि जहां तटबंध हैं और फ्लड कमीशन ने और आवश्यकतानुसार तटबंध बनाने की अनुंशसा की है कि तटबंधों से बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है, उस पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी-बड़ी एवं छोटी नदियां हैं, जो विदेशों से आती है या जिनका यहां ओरिजन होता है, उनका सिल्टेशन हो रहा है, जिसके चलते धाराएं बदल रही हैं, कोर्स बदल रहे हैं। जो पहले एक इलाके में बाढ़ आती थी, अब दूसरे इलाके में बाढ आती है। सरकार को नदियों के रिवर्स के सिल्टेशन पर और जो कोर्सिज चेज हो रहे हैं, जिनके चलते भी बाढ़ आती है, इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। अत: मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं। इस पर सरकार को जोर देना चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Thirunavukkarasar, just seek clarifications. It is converting into a debate.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir, the entire coastal area of Tamil Nadu, particularly the Nagapattinam area, in Pondicherry the Karaikal area and the Andaman and Nicobar Islands were the worst affected by the recent Tsunami. I want to know from the hon. Minister as to how much money was requested by the State Governments of Tamil Nadu and Pondicherry and the Andaman and Nicobar Island. How much money was allotted to them by the Central Government? I want to request the Central Government to allot more funds to these States.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, as far as Bihar and Eastern U.P. are concerned, most of the rivers emanate from Nepal. Now, because of the flooding there, we suffer. There was a proposal about the Sapta Koshi Dam in consultation with Nepal. A survey had been done. In your reply, that aspect has not been dealt with. I want to know from you, through this clarification, whether the Government of India propose to take up completion of these dams expeditiously, with the Government of Nepal, more particularly in the backdrop of the troubled conditions that exist in Nepal. How does the Government propose to go about it? But for this, the trouble keeps on recurring again and again.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हिमाचल में तिब्बत से, बिहार में नेपाल से, अरुणाचल और असम

में चीन से जो दरिया आते हैं, उनके कारण फ्लड आने का खतरा पैदा होता रहता है, पर एक नैचुरल फिनोमिना हो गया है कि जब भी नॉर्थ बिहार में और असम में बाढ़ आती है तो बहुत त्रासदी होती है और हर वर्ष होती है और यह नहीं कि रुक-रुक कर होती है। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कई बार उठी है, तो क्या इसको राष्ट्रीय आपदा, नैशनल कैलामिटी के तहत लाकर, कुछ मदद देकर, इस पर कोई रोक का बंदोबस्त किया जा सकता है?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I would like to begin with the issue raised by Mr. Gavai. It is true that the Government of Maharashtra has sent an initial status report. But they have not sent exactly their total demand for tackling the problem. But it did send us the status report about the overall situation of monsoon in the entire State. In the status report, there was a demand for Rs. 500 crores and the information given by Mr. Gavai is absolutely correct. But till the last week, the overall monsoon rains position has substantially improved and the Government of Maharashtra has indicated that they were going to re-assess the situation and that they were going to send their ultimate or final proposal to us. That is why we are anxiously waiting for that.

Mr. Jairam Ramesh, hon. Member, in his sppech has given certain information regarding certain States and that is factually correct. For instance, he has mentioned about Orissa, Bihar and Jharkhand. It is true that in Orissa, Bihar and Jharkhand, coastal Andhra Pradesh, North-East and a few districts of the Marathwada region of the Maharashtra State, the situation was not at all good. But not the situation has substantially improved. For instance, in the Marathwada region, till today morning, I was trying to contact most of the districts in that region. In the districts like Nanded, the main problem is floods. In the Godavari, practically, the water has flooded the areas and it has gone beyond the danger-level. That is why, there is total concentration of the State and the State machinery in the particular region to save people from the flood. The situation has definitely improved.

It is the same situation is Orissa, Bihar and Jharkhand also. The latest information is, with the overall rainfall, the situation has substantially improved. No State has so far reported drought or drought-like situation due to the deficient water or deficient rainfall during the South-West Monsoon, 2005. So, the situation that has been mentioned here is not there now.

There are certain issues which have been raised especially by Mr. Jairam Ramesh. He sad that the Twelfth Finance Commission has recommended certain recommendations and a point was raised here, which the Government of India has accepted. The Ministry of Finance has accepted the recommendations of the Twelfth Finance Commission concerning the relief matters. So, that issue is also resolved. Another issue raised here was regarding different models of forecasting. The Ministry of Science and Technology is actively looking at and adopting different models of forecasting. In fact, last week only, the concerned Ministry briefed, gave a detailed presentation on what exactly they would like to do in this area. Today stations are limited stations. We are not in a position to get full pictures. Suppose, we select a particular district, we might get information from that particular area. But that is not the reality for the whole district. That is why the thinking of the Ministry of Science and Technology is to adopt different models of forecasting and an assurance has been given by concerned Ministry to the Agriculture Ministry that they would execute the entire programme within two to three years time. I do not think any other important issue was raised regarding drought. The entire discussion was practically concentrated on ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sharad Joshi said something. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, on the first point raised by the hon. Members here, I would like to say that we would like to have the river erosion included in the scheme. We would like the National Disaster Management Authority to look into it. We would like to have it mentioned in the Five Year Plan also. We would like to see that enough funds are provided for this task. This suggestion given by General Chowdhury is correct and we will accept it. I had gone to Gujarat when Gujarat suffered from floods on the next day itself after heavy rains. I could find that the State Government was doing its best. Whatever they had asked for, without waiting even for one hour, on behalf of the Government of India, we agreed to give it to them. They had asked for Rs. 500 crores. We said Rs. 500 crores would be given to them. I did do it after consulting the Prime Minister and the Finance Minister. They said, "What is the amount they are likely to need?" I said, "Much more than Rs. 500 crores. If they are asking for Rs. 500 crores, we should give an assurance that that amount will be given." That was done. Now as far as total amount of money which is

required for rehabilitation is concerned, now, this is something about which they will prepare plans, they will discuss the plans with the Committee which can be constituted here and after that we will decide what amount has to be given to them.

About Himachal Pradesh, this dam really burst and because of that there were floods and because of that people suffered. There were cloudbursts also in that area and because of that also rivers in that area were flooded and people suffered.

Let us not find fault with our neighbouring countries also. I think whatever cooperation was needed, they were willing to give to us. I do not find any plan to create problems for India in what they did.

Mumbai is also suffering, no doubt about it. It is flooded. I had a discussion—Shared Pawarji also had a discussion — with the Chief Minister and other Ministers. I had a discussion with him. We have promised that whatever they need, we will give it to them. They asked for navy boats to be sent to other areas of Maharashtra — Konkan area — those have been given to them. They asked for inflated boats, that arrangement has also been done. They are asking for helicopters, we have done that. In Mumbai they were asking for Army columns to help the people, they have been provided that. We have in one sentence told them whatever assistance they need from the Government of India, we will give it to them. The officers are talking to the officers there. Sharad Pawarji has been talking and I also had discussion with the concerned Ministry. Whatever can be done will be done further. As far as the irrigation schemes are concerned, I do not have specific information. The Minister for irrigation would have that information. If it were necessary I would request him.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: The problem is of irrigation and linking of rivers.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: My entire speech was on irrigation, on dams and on linkages. It was nothing but dams. You are asking for information relating to one dam I have that information. It is readily available in my pocket. I will get it to you. As far as deaths of 300 pesons in Ratnagiri are concerned. I would rather like to think that this would not have happened. I had a discussion with the Chief Minister yesterday. He did give me some information. Probably he is in the process of collecting the information. The correct information will come. We pray that this thing would not have

happened and if it has happened we will take all the steps which are required to help the members of the families of the deceased over there. Let there be no doubt about that. In one word we have told the Government of Maharashtra,"let us know what is required by you and we will try to give that thing from here.' As far as That *bandh* and all those things in Bihar are concerned, that is really a caution. Whenever there is a plain area and big rivers are there and silt are collected, it helps agriculture but it creates problems also like when it gets flooded. At some places they have constructed these dams and *bandhs* and some dams and *bandhs* have also been broken. We would like to see as to how it can be done. The issue, which you have raised, and the issue which was raused by Mr. Thirunavukkarasar are linked. And we will certainly like the Disaster Management Authority to be careful about these things and to prepare plans and let the Government of India and the State Government also know what can be done in this matter. Even siltation is a problem. Some of the rivers which are coming from Himalayas are coming with silt and that silt gets spread in the area and that causes the floods.

This is also a problem. This problem of desiltation and cleaning of rivers was taken up at the time of Shri Rajiv Gandhi. I don't have the details about the exact plans which the Government of India is having now or implementing. This is something which has to be borne in mind. I will certainly convey this thing to the concerned Minister and request him to look into these matters. About Pondicherry, I had discussions with your Chief Ministers, but I don't have the figures with me. If there is anything which has to be done for Pondicherry, we will certainly do. What I have said about Gujarat and Maharashtra and Himachal Pradesh applies to all other places.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Even Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands also.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes, Andaman and Nicobar Islands is a Union Territory and it is with the Home Ministry. We have told them 'whatever is necessary you do it and we will help you from here; it is really a problem that there are some rivers coming from Nepal and we have been discussing this issue with the Government of Nepal. When I had gone there 2-3 times, I had discussions with the Government over there. But this problem is something which has to be handled in a very delicate manner. They have their own views and we have our own views and we would like them to

understand our views and we would like to understand their views also. This is a matter which has not been very easy to solve. The previous Government, the NDA Government was also talking to them and the Government before that also were talking to them. It has not been possible. But, we will continue our efforts to bring about an understanding. The Ministry of External Affairs and the Minister of Water Resources are dealing with the issue of Saptha Koshi Dam, which you have mentioned. I am sure that something is likely to come out of it. Today morning I was told that they were on the verge of agreeing to certain points. But, now, I don't have the details.

Sir, as far as disaster in the Konkan region, which has recevied torrential rains, is concerned, I would say that we shall have to do something extraordinary. The Government of Maharashtra had discussions with the naval officers and the Navel ships have tried to reach those areas. It has not been possible for them to reach by helicpoter and it has also not been possible for them to reach that area by road. So, they have taken the see route and, probably, they have gone and trying to help them. Fortunately, this year, as my colleague, Shri Sharad Pawarji has said, India is not suffering form drought conditions. Wherever there were drought conditions earlier, because of rains, those conditions have disappeared and let us hope that we will have enough and sufficient grains in all areas and drought conditions would not be there.

Hon. Shri Sharad Pawarji has correctly explained that forecasting done by the Meteorological Department is not accurate and the Department has to adopt new methods. Now, the issue of having a super-computer was felt relevant for forecasting at the time of Shri Rajiv Gandhi itself. At that time only we tried to get a super- computer from outside, but we could not. Our Indian scientists said, that they would build a super-computer in India and, at that time, Rajiv Gandhiji allowed them to do that. Fortunately, for us, they have built a super-computer and that super-computer is now used for forecasting weather conditions in India by the Meteorologial Department. But then, new technologies are developing and new things have to be done. Fortunately, for us, the Minister of Science and Technology is seized of the matter and he has agreed and assured the Agriculture Minister that steps are being taken with regard to it.

This is all I wanted to say, Sir. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:The House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at twenty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at tewnty-nine minutes past two of the clock.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in The Chair Short Duration Discussion (Contd.)]

The situation arising due to increasing incidents of cross border terrorism and terrorist acts

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Sir, I tender my apologies for being late by a minute. Actually, it is not my fault: I thought the house would re-assemble at 2.30.

Sir, I do not believe that this is for the first time that we are debating this issue of terrorism and its many manifestations. If is not an occasion that we delight in. It is also not an issue that we like to raise repeatedly beacuse I have observed that on those occasions the debate on this subject has been a saddening experience.

It is much more saddening than it is illuminating. I, certainly, do not see it here as an occasion for rhetorical duels or even for any variety of demonstration of loquacious skills. Sir, I must state clealy that we share the concern. We intiated this discussion for cautioning, warning and sharing with you what our views are, and also for offering you, what in our understanding are some possible ideas, and the challenge that we face under this term-'terrorism'. Today's subject defines it as cross border or internal variety. It is, of course , the internal variety which quite often is a consequences of the cross border; the international terrorism, and it is also what we are witnessing in the country today an ideological extremism. I will come to the details in a minute. Are we witnessing enhanced discontent in the country? Or, is it a kind of mounting, incipient anarchy? We need to, very clearly, understanding the dimensions and the depth of it also. Then, perhaps, these discussions will serve the purpose that, I believe, Parliamentary discussions ought to serve.

Sir, cross border terrorism that we have witnessed is a fallout and a consequence of the play of interests of external powers in our region.

Sir, I will cite the example of Taliban or even, indeed, of Osama Bin Laden. Terror of Taliban and Osama Bin Laden goes back to the 80's and